VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 1385290

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Muktendra kumar

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
Hindi

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

तारीख
Date
27-08-22

केंद्र
Centre
Delhi-
Mukherjee
Nagar

Rit
निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use

परीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of Examiner(s)

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ **Marks Details (To be filled by the Examiner(s))**

प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**		प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**	
1			**11**		
2			**12**		
3			**13**		
4			**14**		
5			**15**		
6			**16**		
7			**17**		
8			**18**		
9			**19**		
10			**20**		
उप-योग (A) Subtotal (A)			**उप-योग (B) Subtotal (B)**		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Do you agree with the view that time has come to revisit the Seventh Schedule of the Indian Constitution? Discuss with suitable arguments. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय शासन व्यवस्था 'संघीय प्रणाली' पर आधारित है, ताकि विविधता भरे राज्यों एवं केंद्र के बीच समन्वय बना कर 'प्रभावी शासन' सुनिश्चित हो सकें। संविधान की 7वीं अनुसूची इसी के अनुरूप है।

7वीं अनुसूची
- → भारतीय संविधान के "अनुच्छेद 246" में इसका प्रावधान।
- → तीन सूची: संघ सूची (100 विषय)
  राज्य सूची (61 विषय)
  समवर्ती सूची: (52 विषय)

पुनर्विचार की आवश्यकता?

(1) केंद्र एवं राज्यों के बीच 'समवर्ती सूची' के प्रयोग को लेकर खींचातानी।

उदाहरण. कृषि कानून २०२०.

(२) उभरते विषयों का समावेश नहीं
उदाहरण. 'डिजिटल संप्रभुता'
'साइबर अपराध'

(३) केंद्र द्वारा राज्य सूची में हस्तक्षेप.
42वां संविधान संशोधन।

(४) 'आपदा प्रबंधन' जैसी प्रविष्टि मौजूद नहीं।

(५) राज्यों को प्रभावी शासन अधिकारों का मुद्दा।

(६) विषयों का स्पष्ट विभाजन का अभाव।

निष्कर्षतः 'लोक हित एवं प्रभावी सुशासन' सुनिश्चित करने के लिए 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए, भारत में इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Highlighting the advantages of online dispute resolution (ODR) mechanism for justice delivery, discuss the challenges associated with its effective implementation in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

'ऑनलाइन विवाद समाधान' से तात्पर्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर न्याय सुनिश्चित करने से है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली 'ई-लोक अदालत' शुरू की है।

लाभ

- 'न्याय शासन' की दूर-दराज तक पहुँच
- 'व्यापक लागत' का कम होना।
- 'कारोबार में सुगमता' को बढ़ावा मिलेगा।
- 'गवाहों' की सुरक्षा के अनुरूप।
- 'समय लागत' का कम होना।

उपस्थित चुनौतियाँ

① 'साइबर सुरक्षा': प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पन्न जटिल चुनौती।

② 'डिजिटल डिवाइड': आईटी इंटरनेट रिपोर्ट द्वारा रेखांकित।

③ प्रतिपादित ढाँचे का अभाव।

④ 'डेटा प्रबंधन' हेतु कानून का अभाव।

⑤ 'ऑनलाइन न्याय' प्रदान करते समय न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने का मुद्दा।

⑥ 'कुशल एवं प्रशिक्षण न्यायधीशों' की आवश्यकता।

निष्कर्षतः उपर्युक्त चुनौतियों को समग्र एवं बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ हल करने की आवश्यकता है ताकि 'अनुच्छेद 39A' का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद, केंद्र-राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रहे हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite the constitutional division of powers, Centre-state disputes have been a perennial feature of Indian democracy. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

मांटेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत को भारतीय संविधान में अपनाया गया है ताकि 'लोकतंत्र' का कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

शक्ति विभाजन
- → अनुच्छेद 50 न्याय शासन का कार्यपालिका से विभाजन।
- → 7वीं अनुसूची
- → अनुच्छेद 121 एवं 122 संसद एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन।

केंद्र-राज्य विवाद

① समवर्ती सूची से विषयों का हस्तांतरण एवं कानूनों का बनना. जैसे: 42वां संविधान संशोधन।

(2) राज्यों का केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप
उदाहरण: CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना।

(3) 'राष्ट्रपति शासन' का प्रयोग एवं राज्यपाल का विलगाव रवैया।

(4) महत्वपूर्ण विधेयकों को धन विधेयकों के रूप में प्रस्तुत करना।
उदाहरण: GST बिल

(5) 'राजकोषीय' मुद्दे उदाहरण: पेट्रोलियम पर शुल्क लगाना।

(6) केंद्रीय एजेंसियों जैसे CBI, BSF का प्रयोग, जिससे राज्य चिंतित है।

निष्कर्षत: संघीय संरचना भारतीय शासन की मूलभूत विशेषता है अत: उपस्थित मुद्दों को अंतर्-सरकारी परिषद्, क्षेत्रीय परिषद् इत्यादि के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

4. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लॉबिंग के लिए एक ढांचे को अंगीकृत करना भारत में सहभागी शासन और कारोबार सुगमता को सुदृढ़ करेगा? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that adopting a framework for lobbying will strengthen participative governance and ease of doing business in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

'लॉबिंग' से तात्पर्य प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव समूहों द्वारा प्रभाव स्थापित करने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। भारत में 'लॉबिंग' को अवैध घोषित किया गया है।

अंगीकृत करना: लॉबिंग ढाँचा?

सहभागी शासन

→ प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने में सहायक।

→ विपरीत मतों पर विचार कर सुदृढ़ नीति तैयार करना

→ प्रशासन में 'लॉबिंग' भागीदार लोकतंत्र को बढ़ावा देगी।

कारोबार सुगमता

1. व्यापारी (कारोबारी) दबाव समूहों से गुणवत्तापूर्ण आँकड़ों का प्रयोग कर प्रभावी आर्थिक नीतियाँ बनाना।
उदाहरण: फिक्की, CMEI इत्यादि

2. अत्यधिक प्रशासनिक कार्यबोझ कम होगी तथा अधिकतम शासन प्राप्त होगा।

हालाँकि इस दिशा में कई चुनौतियाँ है।

चुनौतियाँ
- → प्रशासन को स्वार्थहित का माध्यम बनाना।
- → विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप कर सकता है
- → पश्चिम के विपरीत भारतीय दबाव समूह प्रभावी एवं सुगठित नहीं है

निष्कर्षत: लॉबिंग पर कार्य करने से पहले PPP मॉडल एवं स्थानीय शासन को सशक्त करने जैसे प्रयासों की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. सरकारी अनुप्रयोगों के लिए सरकार द्वारा प्रोपराइटरी (निजी स्वामित्व और नियंत्रण वाली) प्रौद्योगिकी के बजाय ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के बावजूद, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर (FOSS) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite the government encouraging open source instead of proprietary technology for government applications, the true potential of Free and Open Source Software (FOSS) and digital platforms remains unrealized. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कोविड-19 महामारी ने 'डिजिटल शासन' को तीव्र प्रगति प्रदान की है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सरकार द्वारा प्रयोग इस दिशा में देखा जा सकता है।

सरकारी अनुप्रयोग
- → कोविन-प्लेटफॉर्म
- → आरोग्य-सेतु ऐप
- → डिजिलॉकर, डिजीलक्ष्म इत्यादि।

वास्तविक क्षमता के दोहन का अभाव: कारण

① 'डिजिटल अंतराल': ग्रामीण-शहरी

एवं पुरुष-महिला (

② प्रशासन का लालफीताशाही (वैसा, कागजी कार्यवाही) की बढ़ोतरी।

③ निजी क्षेत्र के विपरीत सरकारी प्रशासन में प्रतिस्पर्द्धा का अभाव।

④ इंटरनेट की कनेक्टिविटी एवं साइबर अपराधों का मुद्दा: NCRB के अनुसार 2020 में साइबर अपराधों में 11.8% की बढ़ोतरी हुई।

आगे की राह: 'मिशन कर्मयोगी' का कुशल कार्यान्वयन।

② मजबूत 'डेटा प्रणाली' को सुनिश्चित करना

③ 'डिजिटल अंतराल' को दूर करने हेतु एक सुनिश्चित नीति की आवश्यकता।

ये उपाय अपनाकर 'ई-गवर्नेंस' एवं 'डिजिटल अभिशासन' को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. एक सामाजिक सुरक्षा-वाल्व के रूप में, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) प्रमुख साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से समुदाय अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
As a social safety-valve, non-governmental organisations (NGOs) can be the principal vehicles through which communities voice their concerns. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आँकड़ो के अनुसार भारत मे NGOs की संख्या लगभग 34 लाख है जो शासन मे प्रभावी भूमिका निभाते हैं;

NGOs और सामाजिक सुरक्षा वाल्व.

1. लैंगिक अधिकारो की रक्षा:
AIWDA द्वारा वैवाहित बलात्कार को अपराध घोषित करवाने की दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका।

2. बाल सुरक्षा:
बचपन बचाओ आंदोलन एवं चाइल्डलाइफ केयर इंडिया द्वारा बाल अधिकारो का संरक्षण एवं जागरूकता।

③ WWF इंडिया द्वारा पर्यावरण संरक्षण की मांग।

④ कई गैर-सरकारी संगठन जैसे ADR राजनीति की स्वच्छता का कार्य करते है।

⑤ ऑक्सफैम इंडिया द्वारा असमानता रिपोर्ट का प्रकाशन समुदायों की चिंता को व्यक्त करता है।

⑥ कई गैर-सरकारी संगठन वृद्धों की चिंताओं को उठाते है जैसे:
रिया फाउंडेशन

निष्कर्षतः गैर-सरकारी संगठन लोक कल्याण को सुनिश्चित करने मे काफी सहायक होते है, जिनके कार्यों की सराहने के साथ-साथ भागीदार बनने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. अपने रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सराहे जाने के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का कार्यान्वयन सुस्त है और विभिन्न मुद्दों से घिरा हुआ है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite being lauded for its patient centric approach, the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017, remains sluggish and mired with various issues. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक अवसादग्रस्त देश है, इस संदर्भ में मानसिक देखभाल अधिनियम 2017 बेहद आवश्यक है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधि. 2017 प्रावधान

→ प्रत्येक नागरिक तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को सुनिश्चित करना

→ समुदायों के बीच मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना।

→ समावेशिता दृष्टिकोण अपनाना।

हालांकि यह काफी कुन्द बना हुआ है, (कार्यान्वयन)

मुद्दे

① स्पष्ट रणनीति का अभाव।

② मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों का अभाव, केवल 9,000 उपलब्ध

③ बढ़ता मानसिक तनाव, लगभग 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता।

④ प्रशासन की उदासीन रवैया।

⑤ महामारी ने इस कानून की आवश्यकता को और बढ़ाया है।

निष्कर्षतः इस अधिनियम की कमी को दूर करते हुए "योग" को लोगों के दैनिक जीवन का भाग बनाने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है ताकि "SDG 3" को प्राप्त किया जा सके।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार करने का समय आ गया है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that time has come to formulate an Urban Employment Guarantee scheme at the national level? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

"PLFS" द्वारा जारी हालिया आँकड़े दर्शाते हैं कि शहरी बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में विश्लेषक शहरी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा की तर्ज पर की आवश्यकता बता रहे हैं।

शहरी बेरोजगारी एवं मुद्दे

① शहरों में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी

② प्रवासन के कारण रोजगारों का अभाव।

③ शहरी बाढ़ जैसी आपदा रोजगार को छीन लेती है।

(4) शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा रोजगार सृजन को पर्याप्त बढ़ावा न दिया जाना।

(5) वैश्वीकरण ने बाजारों को खोल दिया है जिससे भारतीय उद्योग प्रभावी हुए हैं, तथा बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है।

हालांकि शहरी रोजगार गारंटी योजना की राह में कई चुनौतियाँ हैं

चुनौतियाँ
- → सरकार पर बढ़ता सब्सिडी बोझ
- → मुद्रास्फीति को बढ़ावा।
- → अकर्मण्यता का भी संदेह।

निष्कर्षतः शहरी बेरोजगारी हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी योजनाओं को तीव्रता एवं कुशलता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए एवं शहरी गारंटी योजना अंतिम उपाय के रूप में लाई जानी चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्सटेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of BIMSTEC as a regional organisation to fulfil India's strategic aspirations in the Indian Ocean Region. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में बिम्सटेक द्वारा 'चार्टर' को अपनाया गया है, जिसके कारण यह चर्चा में है।

बिम्सटेक
- → 1997 की बैंकॉक घोषणा से स्थापना।
- → 7 सदस्य देश
- → मुख्यालय: ढाका।
- → तकनीकी, राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन।

बिम्सटेक का भारत हेतु सामरिक महत्व:
हिंद महासागर में।

(1) बिम्सटेक देशों के साथ 'व्यापार' को बढ़ावा देकर

चीन की चेक डिप्लोमेसी को काउंटर करना।

(2) हिंद महासागर में समुद्री डकैती जैसे अपराधों को प्रबंधित करना।

(3) आपसी तकनीकी सहयोग द्वारा तकनीकी क्षमता प्राप्त करना।

(4) 'सार्क' की सुप्त अवस्था में दक्षिण एशिया का नेतृत्व।

(5) 'एक्ट ईस्ट एशिया' नीति के अनुरूप हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बनाए रखना।

(6) 'ऊर्जा सुरक्षा' के क्षेत्र में कार्य करना।

निष्कर्षतः बिम्सटेक की निष्क्रियता को भारत को सक्रियता में बदलकर हिंद महासागर में अपने 'सामरिक हित' सुनिश्चित करने चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. वर्तमान समय में अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में भारत के लिए गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of the Gujral Doctrine for India with regard to its relations with its immediate neighbours in the present times. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है ऐसे में भारत का अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलना एवं उपमहाद्वीप की समृद्धता को बनाए रखना आवश्यक है। गुजराल सिद्धांत इसी दिशा में प्रभावी सिद्धांत है।

गुजराल सिद्धांत
→ पड़ोसी देशों के साथ गैर-पारस्परिक संबंध
→ देशों को अपनी भूमिका इस्तेमाल करके देशों के विरुद्ध न करना।
→ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
→ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं पारस्परिक लाभ।

प्रासंगिकता

① चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी।

② भारत द्वारा मधेसी संकट में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को घटाने में यह सिद्धांत सहायक।

③ 'श्रीलंकाई संकट' के दौर में श्रीलंका को भारत हित धारित दृष्टिकोण अपनाने हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग बेहद जरूरी।

④ पड़ोसी देशों में संकट का प्रभाव भारत पर भी पड़ता है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि को लाइन ऑफ क्रेडिट इत्यादि प्रदान करना।

निष्कर्षतः भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने हेतु पड़ोस को सहजता एवं समग्रता से साथ लेकर चलने में गुजराल सिद्धांत सहायता कर सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. भारतीय संसदीय प्रणाली में "संसद के अधिकारियों" की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Highlight the pivotal role of the "Officers of Parliament" in the Indian Parliamentary system. Also, discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

"संसद के अधिकारी" संसद की सुचारु कार्यवाही को सुनिश्चित करते है। इनकी भूमिका निम्न लिखित है।

(1) मंत्रियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना।

(2) 'संसद सदस्यों' को आवश्यक सूचना प्रश्न प्रदान हेतु प्रदान करना,

(3) संसदीय कार्यवाई को सुनिश्चित बनाए रखना।

(4) संसद की कार्यवाही के आंकड़ों का संग्रहण एवं अपडेट।

संसदीय अधिकारियों के निष्पक्ष कामकाज हेतु प्रावधान:

(1) संवैधानिक प्रावधान

- लोक सभा सचिवालय निष्पक्षता से कार्य करेगा।
- राज्य सभा सचिवालय निष्पक्षता एवं ईमानदारी से कार्य करेंगे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② वैधानिक प्रावधान

'संसदीय सचिव' का प्रावधान ताकि संसद को और प्रभावी बनाया जा सके।

निष्कर्षतः 'लोकतंत्र के मंदिर' को प्रभावी बनाने में संसदीय अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Finance Commission plays a crucial role in balancing fiscal federalism in India. In this context, examine the recommendations given by the 15th Finance Commission. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उत्तर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है जो एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है।

FC की राजकोषीय संघवाद में भूमिका

- करों का संवैधानिक वितरण सुनिश्चित करना।
- राज्यों एवं स्थानीय निकायों को राजस्व अनुदान की सिफारिश करना।
- राज्यों की सिफारिश पर स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों के संवर्द्धन हेतु सिफारिश करना।

15वे वित्त आयोग की सिफारिशे :

डॉ एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वे वित्त आयोग ने निम्न सिफारिशें की है।

1. कर राजस्व का 41% राज्यों को ऊर्ध्वाधर वितरण।
2. जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश हेतु 1% वितरण।
3. आपदा प्रबंधन फंड को बनाने की सिफारिश।
4. स्थानीय निकायों हेतु राजस्व अनुदान
5. राज्यों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना क्षेत्र में पर GDP का 8% खर्च करने की सिफारिश।
6. 'जिला अस्पतालों' को सुविधा प्रदान करने के लिए PPP मॉडल की सिफारिश।

सिफारिशों का परीक्षण।

लाभ → केंद्र राजस्व वितरण प्रणाली पहले की तरह स्थिर है, महामारी के बावजूद।

राज्यों को 'स्वास्थ्य प्रणाली' को मजबूत करने में सहायता प्राप्त होगी।

चिंताएँ → 2011 के आँकड़ों का प्रयोग जिसे लेकर दक्षिणी राज्य चिंतित है।

केंद्र की उपकरों एवं अधिभारों पर बढ़ती निर्भरता को प्रबंधित करने हेतु कोई सिफारिश नहीं।

निष्कर्षतः 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 'संकट ऑफ गॉड' के समय में सार्थक है, उपस्थित चुनौतियों को विवेकशीलता से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में योगदान करेगा। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Critically assess whether according statutory backing to the Model Code of Conduct will contribute towards free and fair elections in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का प्रावधान किया गया है। आदर्श आचार संहिता इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है।

MCC और वैधानिक समर्थन ?

① 'मुफ्त की सौगात' को नियंत्रित करने हेतु 2016 में बनाए गए प्रावधानों का कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

② 'आंतरिक-दल लोकतंत्र' को सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग को शक्तियाँ मिलेंगी।

③ 'राजनीति का अपराधीकरण' को कम किया जा सकेगा; ADR: 2009-19 (आपराधिक पृष्ठभूमि के बीच संसद में वाले सांसद) 109% की वृद्धि

(7) छोटी पार्टियों को समान मंच प्रदान होगा।

(8) चुनाव की पवित्रता सुनिश्चित हो सकेगी।

हालांकि इस दिशा में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

चुनौतियाँ

- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाद 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की सीमाओं को स्वीकारा
- दल-बदल कानून में विद्यमान खामियाँ जिससे MCC को वैधानिक समर्थन देना अद्भुत कार्य
- मतदाता जागरूकता का अभाव

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आगे की राह: दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति की सिफारिशों को लागू करना MCC को वैधानिक समर्थन से पहले, जरूरी है।

↳ 'नागरिक समाज' जैसे ADR द्वारा 'मतदाता जागरूकता' को बढ़ावा देना।

↳ 'वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं' से सीखना जैसे: जर्मनी जहाँ राजनीतिक पार्टियों को संवैधानिक मान्यता दी गई है।

↳ MCC को लेकर पार्टियों को संवेदनशील बनाना।

'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव' लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए इसे सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. डिजिटल क्रांति के कारण बाजार में आए व्यवधान ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नवीकृत फोकस और परिप्रेक्ष्य को आवश्यक बना दिया है। इस आलोक में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में सुधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The market disruption caused by digital revolution warrants renewed focus and perspective to ensure fair competition in the digital economy. In this light, discuss the need to revamp the Competition Commission of India (CCI). (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

डिजिटल भुगतान सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्कोर लगभग 350 हो गया है, जो 'डिजिटल क्रांति' को दर्शाता है

व्यवधान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा:

(1) GAFA कंपनियों का डिजिटल व्यापार पर कब्जा।

(2) छोटे एवं नवीन स्टार्टअप्स की बाजार पहुँच बेहद कम।

(3) 'कार्टेलाइजेशन' का प्रयोग एक बड़ी चिंता।

ऐसे में प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका बेहद आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो जाती है।

CCI
- → कानूनी संस्था
- → बाजार में प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना मुख्य कार्य
- → बाजार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना।

सुधारों की आवश्यकता: CCI

(1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में आधुनिकतम तकनीकों जैसे: कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं ब्लॉकचेन से लैस प्रशासकों का अभाव।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(7) 'निजता कानून' के अभाव के चलते इनकी शक्तियाँ सीमित।

(8) MNCs द्वारा कानूनों के दुरुपयोग का प्रयोग करना, जिसे पकड़ने में CCI कमजोर।

क्या सुधार हो?

→ CCI को कुशलतम एवं विशेषज्ञतापूर्ण कर्मचारी ही चलाएं।

→ प्रतिस्पर्धा अधिनियम को अन्य कानूनों जैसे कंपनी अधिनियम से समन्वय।

→ भारतीय कंपनियों, विशेषकर स्टार्टअप्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान।

ये भारत बाजार की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. भारत में एक प्रभावी व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र और साथ ही यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्हिसल-ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

There is an urgent need for effective whistle-blowing mechanisms and ensuring that necessary safeguards for the protection of whistle-blowers are established in both public and private spheres in India. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

'भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024' में भारत को 180 देशों में 85वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, इससे निपटने के लिए भारत में एक प्रभावी व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र बेहद आवश्यक है।

प्रभावी व्हिसल ब्लोइंग हेतु प्रावधान

① व्हिसल ब्लोइंग अधिनियम 2014

- यह अधिनियम व्हिसल ब्लोअर को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- व्हिसल-ब्लोअर की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र की आवश्यकता

(1) प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने हेतु।

(2) कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रभावी बनाने हेतु: हाल ही में NSE स्कैम के चलते पर बेहद आवश्यक।

(3) प्रतिस्पर्धा एवं वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने हेतु आवश्यक।

व्हिसल-ब्लोअर्स: सुरक्षा मुद्दा ०

(1) बदला लिए जाने की भावना से सुरक्षा।

(2) सत्येंद्र दुबे जैसी ईमानदार अफसर व्हिसल-ब्लोअर्स की सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रावधान न होने के कारण नहीं रहे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सुरक्षा उपाय

(1) WPA श्रम में सुरक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधान सुनिश्चित करना।

(2) एक पृथक एजेंसी का निर्माण, जो व्हिसल-ब्लोअर्स प्रणाली को प्रबंधित करे।

(3) नागरिक समाज का सहयोग सुनिश्चित करना।

(4) गोपनीयता बनाए रखने के लिए मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करना।

जैसा कि चाणक्य का कहना है कि भ्रष्टाचार राज्य के लिए एक दीमक है, अतः इस दीमक को हटाने हेतु प्रभावी व्हिसल-ब्लोविंग बेहद आवश्यक है, जो सुरक्षित भी हो।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. भारत में सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इनकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
State the reasons behind the poor performance of cooperatives in India. Also, discuss the reforms undertaken by the government to overcome the shortcomings. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सहकारी समितियां लोगों का एक स्वैच्छिक समूह होती है, जो किसी साझे उद्देश्य हेतु साथ आते हैं।

खराब प्रदर्शन के कारण

- सहकारिता सहकारी समितियों के कर्मचारियों में प्रबंधन कुशलता का अभाव।
- सहकारी समितियों पर अभिजात्य वर्ग का नियंत्रण।
- सरकार की स्पष्ट नीति का अभाव।
- फंड की कमी एवं जागरूकता का अभाव।

सुधार हेतु सरकारी प्रयास

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

① सहकारी मंत्रालय की स्थापना। यह सहकारिता को बढ़ाने में सहयोग करेगा।

② 97 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(c) एवं अनुच्छेद 43(B) को समाहित किया गया।

③ सरकार एक नई "सहकारिता नीति" लाने की तैयारी में है।

④ "एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड" के तहत कृषि समितियों को सहायता।

(5) 100 वाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मानकर सहकारी समिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

(6) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 द्वारा सहकारी बैंकों को RBI के तहत रखकर प्रबंधन की कुशलता सुनिश्चित करना।

निष्कर्षत: सहकारी समितियाँ गांधीजी के 'ग्राम स्वराज' एवं सबका साथ, सबका विकास के अनुकूल तंत्र है, जिनकी कमियों को दीर्घ दृष्टिकोण के साथ हल किये जाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए, तो इसमें भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विद्यमान अंतराल को पाटने की क्षमता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Public-Private Partnership model, if harnessed properly, has the potential to bridge the gaps in India's healthcare system. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है, किंतु इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य के पास क्षमता का अभाव है, ऐसे में PPP मॉडल लाभदायक हो सकता है।

स्वास्थ्य प्रणाली में अंतराल

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत GDP का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करने का प्रावधान जो वर्तमान में 2% से कम है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कुल अस्पतालों का मात्र 20% उपलब्ध, जबकि गाँवों में 68% जनसंख्या

③ गरीबों का स्वास्थ्य व्यय आय का 10%. जबकि अमीरों का 2%.

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PPP मॉडल: स्वास्थ्य क्षेत्र: (लाभ)

① निजी क्षेत्र की कुशलता एवं 'प्रतिस्पर्धी संस्कृति' से सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकेगा।

② महामारी जैसी आपातकाल परिस्थितियों में कुशल एवं तीव्र कार्यवाई।

③ राज्य की राजस्व क्षमता का पूरक बन सकता है PPP मॉडल।

④ ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर करने में लाभ मिलेगा. "स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र" की क्षमता बढ़ेगी।

(4) आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी योजनाओं का सुलभ एवं तीव्र कार्यान्वयन हो सकेगा।

हालाँकि निजी क्षेत्र केवल लाभ के लिए कार्य करता है किंतु स्पष्ट एवं निर्दिष्ट नीति के तहत इसे 'लोक कल्याण' हेतु प्रभावी बनाया जा सकता है,

इसके अलावा "स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022" पर विचार किया जा सकता है

"स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, न कि सोने-चाँदी के टुकड़े।"

- गांधीजी

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

18. यद्यपि नई शिक्षा नीति अपने साथ एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लेकर आई है, इसकी सफलता सरकार की अन्य नीतिगत पहलों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Although the New Education Policy brings with itself a commendable vision, its success will depend on its ability to effectively integrate with the government's other policy initiatives. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

'शिक्षा' संपूर्ण मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी तत्व है, नई शिक्षा नीति इसी का शिक्षा में प्रभावी कदम है।

NEP 2020: प्रशंसनीय दृष्टिकोण।

1. 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' पाँच स्तंभों में से एक।
2. '10+2' प्रणाली के स्थान पर '5+3+3+4' प्रणाली को अपनाया गया है।
3. कक्षा 5 तक यदि आवश्यक हो तो 8 तक क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा में शिक्षा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

④ कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा

⑤ उच्च शिक्षा हेतु MERU की स्थापना का प्रावधान।

⑥ 'लैंगिक अंतराल फंड' की उपस्थिति।

⑦ विदेशी शिक्षा संस्थानों को खोलने की अनुमति।

सफलता हेतु नीतिगत पहलों के साथ एकीकृत होने की आवश्यकता

① राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का कार्यान्वयन, ताकि स्वस्थ एवं शिक्षित युवा अर्थव्यवस्था बन सके।

② राज्यों को प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपना।

③ 'त्रिभाषा-फॉर्मूला' को सुनम्य तरीके से अपनाना।

(4) वंचित तबकों एवं पिछड़ों को स्कूली शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करवाना।

(5) PM पोषण शक्ति योजना का प्रभावी एवं समावेशी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(6) उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।

निष्कर्षतः "SDG-4" को प्राप्त करने एवं वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने हेतु भारत को शिक्षा नीति 2020 को मजबूत एवं समन्वित तरीकों से लागू करने की आवश्यकता है।

"शिक्षा व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र है : चाणक्य"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न हुआ है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में भारत की चिंताओं की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) is born from a collective desire to make the Indo-Pacific region an engine of global economic growth. Comment. Also, discuss India's concerns in this context. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में जापान में आयोजित हुई क्वाड की बैठक में IPEF बनाने की बात हुई है जिस पर भारत भी सहमत है।

IPEF
- → आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना।
- → 14 सदस्य देश
- → यह रणनीतिक संगठन होगा।

हिंद-प्रशांत को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाना : IPEF

(1) हिंद-प्रशांत में भारत विश्व की सबसे तेजी से संवृद्धि करते

वाली अर्थव्यवस्था है वही अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

(2) ASIAN देशों का बाजार।

(3) इन देशों (IPEP) के आर्थिक विकास हेतु 4 स्तंभ अपनाए गए है।

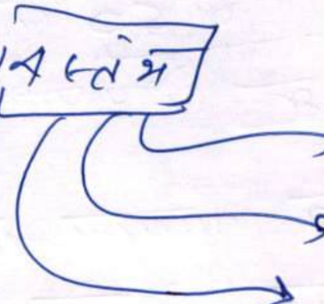

→ जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था
→ स्वच्छ अर्थव्यवस्था
→ लचीली अर्थव्यवस्था
इत्यादि।

(4) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र: दुर्लभ खनिजों, बड़ा बाजार, युवा आबादी की उपस्थिति से आर्थिक विकास तेजी से होगा।

हालांकि इन सबके बावजूद IPEF में स्पष्टता का अभाव है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि B3W की तरह यह भी स्पष्ट नहीं है।

भारत की चिंताएँ

- सीमा पार डेटा प्रवाह का प्रावधान, इसके कारण भारत ओसाका ट्रैक से भी बाहर हो गया था।
- मजबूत श्रम व पर्यावरण मानकों का प्रावधान, जिनसे भारत बचता रहा है।
- "अमेरिकी हितों" को यह व्यवस्था वरीयता देती है।

निष्कर्षतः "IPEF" RCEP के प्रभाव को कम कर हिंद-प्रशांत की भू-अर्थव्यवस्था का केंद्र बना सकती है लेकिन इसे आपसी मतभेदों को दूर करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. विस्तृत होते डिजिटल स्पेस और नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं के बीच भारत को अपनी तकनीकी-कूटनीति (टेक्नो-डिप्लोमेसी) को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India needs to identify the priority areas to further its techno-diplomacy amidst the complexities of expanding digital space and New and Emerging Strategic Technologies. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक कूटनीति, सॉफ्ट कूटनीति, बल कूटनीति का ही प्रचलन रहा है किंतु वर्तमान परिवेश तकनीकी-कूटनीति की नई प्रणाली को लेकर आया है जो भारत की विदेश नीति हेतु बेहद आवश्यक है।

विस्तृत डिजिटल स्पेस और उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी।

(1) आम जन तक डिजिटल सुविधाओं को पहुँच, उदाहरण: मोबाइल बैंकिंग।

(2) कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन जैसी सामरिक प्रौद्योगिकी।

बाधाएं → कुशल एवं प्रभावी 'डिजिटल अभियान' एवं डिजिटल फोर्स का अभाव।

→ 'डिजिटल साक्षरता' का अभाव।

तकनीकी कूटनीति और प्राथमिकता वाले क्षेत्र

① विदेश मं० ने NESP डिवीजन की स्थापना की है।

② 'द्विपक्षीय समझौते' सामरिक प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के लिए किए गए हैं।

③ भारत को 'सॉफ्ट पावर' का प्रयोग कर भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार 'तकनीकी कूटनीति' द्वारा किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

④ "डेटा की सुरक्षा साइबर आक्रमणों" जैसे डीप-फेक, से सुरक्षित रहने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाया जा सकता है।

⑤ 'व्यापार' को बढ़ावा देने के लिए 'तकनीकी-कूटनीति' बेहद आवश्यक।

⑥ 'विश्व की कौशल राजधानी' बनने के लिए तकनीकी-कूटनीति द्वारा वैश्विक देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना।

इन क्षेत्रों पर फोकस कर तकनीकी कूटनीति को बढ़ाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK